



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया।

'आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई हो'

तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक में मु.मंत्री ने कहा

जयपुर, 24 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा एवं त्वरित न्याय देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। साथ ही, गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में कई

■ प्रभावी निगरानी के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं - मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि गृह विभाग से जुड़े शत प्रतिशत कार्मिकों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियों से संपत्तियां अर्जित करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियां जब्त की जाए, जिससे उनके हॉसले परत हों। उन्होंने प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के फिंगरप्रिंट लेने एवं ई-सम्पन्न को प्रभावी तामील करने के निर्देश दिए, ताकि अपराधियों पर सतत निगरानी के साथ प्रभावी निर्यंत्रण भी रहे। उन्होंने कहा कि नवीन कानूनों में पहली बार के अपराधी की एक तिहाई सजा पूर्ण होने पर रिहा

करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में संवेदनशीलता रखते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए।

शर्मा ने गृह विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं पदोन्नत करने के निर्देश दिए, ताकि पर्याप्त मानव संसाधन के नियोजन से प्रदेश के हर क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा। उन्होंने कहा कि गृह विभाग आगामी वर्षों में रिक्त होने वाले पदों का भी पूर्ण विवरण तैयार करे, ताकि कार्मिक के सेवानिवृत्त होते ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गत दिनों केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा ली गई बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुसार नए कानूनों के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस के कुल 84 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को नवीन कानूनों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 98.5 प्रतिशत जांच

अधिकारी भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। नए कानूनों के तहत प्रदेश में अब तक 1 लाख 12 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 75 हजार से अधिक का निस्तारण भी किया जा चुका है। इस दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण, ज़ीरो एफआईआर, ई-साक्ष्य जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा की गई।

बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य ब्रजेन्द्र कुमार जैन, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, पुलिस महानिदेशक कारागार गोविंद गुप्ता सहित पुलिस, अभियोजन, फॉरेंसिक एवं कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्टालिन ने मोदी से सीख ली: अभी...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेण)

वादों को पूरा करने पर है। सोमवार को एम.के. स्टालिन ने राज्यभर में एक हजार मुख्यमंत्री फार्मसी लॉन्च कीं, जिनके द्वारा जनता को रियायती दरों पर दवा मिलेगी।

इस पहल का यह पहला भाग है, बाद में अन्य मैडिकल सेवाओं के लिए भी ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी। मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए बनाई गई इस योजना का लक्ष्य है, उन लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध करवाना, जो निजी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं।

स्टालिन ने डायाबिटीज व हाइपरटेंशन जैसी क्रॉनिक बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाओं को ऊँची

कीमतों को देखते हुए कहा था कि इसके लिए वे एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे।

अब इन मुद्दालवर मरुन्धगाम में जैनरिक व आवश्यक दवाएं कम दाम पर मिलेगी। इन फार्मसी को चलाने वाले फार्मासिस्ट व कोऑर्परेटिव सोसायटीज को सरकार 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसके अलावा, दवाएं 75 प्रतिशत कम दाम पर मिलेगी, जिससे वैद्य सेवा ज्यादा सरल हो जाएगी।

नई शुरू की गई 1000 फार्मसीज में से 500 का प्रबंध कोऑर्परेटिव सोसायटी देखेंगी तथा 500 अन्य का प्रबंधन प्रशिक्षित फार्मासिस्ट व व्यवसायी करेंगे।

स्टालिन ने दोहराया कि द्रमुक

सरकार हेल्थ और एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे जितनी भी आर्थिक मुश्किलें क्यों न हों।

उन्होंने कहा, ये योजनाएं सिर्फ तमिलनाडु की जनता की भलाई के लिए हैं। केन्द्र सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद इन्हें रोका नहीं जाएगा।

स्टालिन का इरादा साफ है, अपनी सरकार के लिए समर्थन जुटाना, साथ ही वे यह समझाना भी चाहते हैं केन्द्र सरकार राज्य को मदद नहीं कर रही है बल्कि प्रतिबंध लगाकर विकास में अड़ौंगे ला रही है।

उन्हें व उनकी पार्टी और सरकार को पर्याप्त मीडिया समर्थन मिल रहा है, इसलिए, कांग्रेस के विपरीत, उनके लिए भाजपा व केन्द्र विरोधी कथानक पेश करना आसान है।

'मखाना सुपरफूड, में 300 दिन खाता हूँ'

पटना, 24 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार की एक दिवसीय यात्रा पर सिलिक सिटी के रूप में मशहूर भागलपुर पहुंचे। उन्होंने भागलपुर में आयोजित पीएम किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जहां बिहार को केन्द्रीय बजट में दिए गए मखाना बोर्ड की चर्चा की, वहीं मखाना को सुपर फूड बताते हुए इसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के किसानों को खुशियों की सीमाएं देते हुए पीएम किसान सम्मान योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जहां किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गिनाया।

राहुल गांधी को बाजवा पर नज़र रखने की नसीहत दी आप ने

चंडीगढ़, 24 फरवरी। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जाना लगभग तय है। अरोड़ा ने सोमवार को कहा कि बाजवा ने पहले ही भाजपा के साथ अपनी 'एडवांस बुकिंग' पक्की कर ली है। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूँ कि वह बाजवा से सवाल करें कि उन्होंने हाल ही में बंगलुरु में भाजपा के किन वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसा लगता है, जैसे उनकी 'स्क्रिप्ट' भाजपा कार्यालय में तैयार की गयी है, बिल्कुल उनके भाई की तरह, जो पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

नाबालिग आदतन अपराधी को सुप्रीम कोर्ट का जमानत से इन्कार

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने नाबालिग के अपराधिक इतिहास पर गौर करने के बाद यह फैसला लिया

नयी दिल्ली, 24 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने बार-बार अपराध करने के आरोपी एक नाबालिग को जमानत से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि उसकी उम्र के कारण ही उसे कानून से छूट नहीं मिलेगी। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने नाबालिग के अपराधिक इतिहास पर गौर किया और बताया कि उसके खिलाफ चार समान मामले दर्ज हैं। पीठ ने पहले से ही तीन अन्य मामलों में जमानत पर चल रहे

याचिकाकर्ता से कहा कि किशोर अपनी उम्र की आड़ में बार-बार नतीजों से बच नहीं सकता। वह सुधारने लायक नहीं है! वह सुधारने लायक नहीं है।

जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के मौजूदा मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। वर्तमान मामले के संदर्भ में यह स्वीकार करते हुए कि आरोपी किशोर कानून के तहत अधिकतम तीन साल की सजा के आधे से अधिक (एक वर्ष और आठ महीने)

से हिरासत में है, न्यायालय राहत देने के लिए सहमत नहीं हुआ। पीठ ने इसके अलावा, गवाहों की गैर-मौजूदगी के कारण मुकदमे की कार्यवाही में देरी पर ध्यान दिया और किशोर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने शीघ्र सुनवाई का आदेश देते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि आरोपी आवश्यक हो तो रोजाना सुनवाई करके चार महीने के भीतर अदालती कार्यवाही पूरी की जाए।

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षा 2022 पेपरलीक के आठ अभियुक्तों की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज

गत गहलोल सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित, लोकसेवा आयोग, द्वारा द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षा 2022 अभियुक्तों की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

जयपुर, 24 फरवरी। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षा 2022 के पेपरलीक से जुड़े आठ अभियुक्तों की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

गत गहलोल सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गहलोल सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित अन्य परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी पेपरलीक हो गया था।

इस प्रकरण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज पुत्र स्व. प्रेमलाल विशनोई, राजीव कुमार पुत्र स्व. प्रेमलाल विशनोई, रामगोपाल मीणा, गोपाल सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह कपरुवान राजपूत, विजयराज वर्मा पुत्र वरिंगराम वर्मा, राजीव विशनोई पुत्र भगवानाराम विशनोई की जमानत याचिका खारिज हुई।

विजेन्द्र गुप्ता...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेण)

किया। अध्यक्ष के लिए दूसरा प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदरज सिंह ने किया, जिसका मंत्री प्रवेश वर्मा ने समर्थन किया। भाजपा विधायक कुलवंत राणा ने भी गुप्ता के लिए अध्यक्ष पद के दोनों प्रस्तावों का समर्थन किया।

प्रोटेम स्पीकर अरविंद लवली ने गुप्ता का नाम अध्यक्ष के लिए सदन के समक्ष रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आशिषी ने गुप्ता को अध्यक्षीय आसन तक पहुंचाया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

■ इस प्रकरण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विशनोई की जमानत याचिका खारिज हुई।

गोपाल सिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह कपरुवान राजपूत, विजयराज वर्मा पुत्र वरिंगराम वर्मा, राजीव विशनोई पुत्र भगवानाराम विशनोई की जमानत याचिका खारिज हुई।

एस.ओ.जी. के ए.डी.जी., वी.के. सिंह के अनुसार अभियुक्त पुखराज विशनोई ने लेपटॉप एवं प्रिन्टर के माध्यम से सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक विषय के पेपरों के प्रिन्टआउट तैयार कर उदयपुर के एक होटल में सात अपाध्ययों को परीक्षा से पहले उपलब्ध कराये। इसके अलावा, उसने एक बस में 41 परीक्षार्थियों को भी ऐसे ही पेपर प्रिन्टआउट अभियुक्त पीराराम

विशनोई के माध्यम से उपलब्ध कराये थे। अभियुक्त रवि कुमार ने अभियुक्त भूपेन्द्र सारण की मदद से जयपुर के एक होटल में अभियुक्तों को लोक पेपर उपलब्ध कराये थे। अभियुक्त गमराम खिलेरी पटवारी के पद पर नियोजित थे।

एस.ओ.जी. की रिपोर्ट के अनुसार, भूपेन्द्र सारण के माध्यम से अभ्यर्थी सुनील को एक बस में पेपर उपलब्ध कराये थे। गमराम खिलेरी के निरुद्ध ब्यूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल करवाने के आरोप में कनिष्ठ लेखाकार एवं राज्य लेखाकार भर्ती परीक्षा के संबंध में वर्ष 2015 में

राजसमंद, गोगुन्दा, कांकोरोली एवं एस.ओ.जी. जयपुर में भी प्रकरण पंजीबद्ध हुये थे एवं इन प्रकरणों में इसे गिरफ्तार किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अनिता मीणा जयपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंधक के पद पर नियोजित थीं। अनिल कुमार मीणा द्वारा पेपरलीक से अर्जित अवैध धन (19.50 लाख रुपये) का निवेश अनिता मीणा के नाम चल-अचल संपत्ति में किया गया था। राजीव विशनोई अध्यापक के पद पर नियोजित था।

इसने पेपरलीक गिरोह के सक्रिय सदस्य ओमप्रकाश ढाका परीक्षार्थी महेन्द्र प्रजापत एवं नागराज को बेकरीया बस में पेपर उपलब्ध करवाने में मदद की थी। इसे उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में भी गिरफ्तार किया था।

'आप के 32 विधायक...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेण)

नुकसान के बाद, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द किशोर ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित, पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई है।

ज्ञातव्य है कि आप को उस समय जबरदस्त धक्का लगा था, जब 10 साल सत्ता में रहने के बाद, वह दिल्ली विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। इन चुनावों में, जहाँ भाजपा को 48 सीटें मिली थीं, वहीं आप 22 सीटों पर सिमट गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपकी पराजय की घुबूमि में, सब की नजरों में इस मीटिंग को बुलाये जाने को लेकर उत्सुकता एवं बेचैनी है। भाजपा

ने कहा है कि इस मीटिंग का उद्देश्य मान को मुख्यमंत्री पद से हटाना है। इस बीच, आप ने कहा है कि इस मीटिंग का एजेंडा पार्टी की कमियों का विश्लेषण करना है। कांग्रेस, पंजाब में सत्तारूढ़ आप के अंदरूनी तनाव एवं विभाजन पर जोर देते हुये, पार्टी पर दबाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली की सत्ता खोने के बाद, आप की लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है। सूत्रों का कहना है कि कई आप विधायक, जो पिछले विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुये थे, मुख्यमंत्री मान की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि मान की अपनी अलग ही सनकें एवं दिलचस्पियाँ हैं।

दिल्ली विधानसभा में पहले दिन ही भारी हंगामा

नई दिल्ली, 24 फरवरी। दिल्ली विधानसभा में सत्र के पहले ही दिन सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दिल्ली की आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में तीन बार के भाजपा विधायक विजेन्द्र गुप्ता को स्पीकर चुना गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष आशिषी ने विजेन्द्र गुप्ता को बधाई देते हुए भाजपा पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाने का आरोप लगाया।

उन्होंने भाजपा को दलित और सिख विरोधी बताया, वहीं, गुप्ता ने आशिषी के बयान की निंदा की और उन पर माहोल खराब करने का आरोप लगाया। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष आशिषी ने विजेन्द्र गुप्ता को शुभकामनाएं देते हुए भाजपा पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली विधानसभा का नेतृत्व एक ऐसी पार्टी कर रही है जो दलित और सिख विरोधी है।"

फड़नवीस ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेण)

कुछ सप्ताहों से शिंदे मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों से नदारद रहते हैं। शिंदे कटाक्ष करने में भी पीछे नहीं हैं। हाल ही में नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि "मुझे हल्के में न लिया जाए। पिछली बार मुझे हल्के में लिया गया था तो 2022 में मैंने सरकार गिरा दी थी और जनता की इच्छा के अनुसार, डबल इंजन सरकार लाया था। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ, पर बाला साहेब ठाकरे का अनुयायी हूँ, लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए।"

पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर शिंदे ने अपनी टिप्पणी, "मुझे हल्के में न लें" को मामूली बात बताते हुए कहा कि यह टिप्पणी दो साल पहले हुई एक घटना के बारे में थी।

संभल ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेण)

सभी तरह कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। मस्जिद समिति ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्र में प्राचीन कुओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास में धार्मिक अनुष्ठान कर रही है और यह कुआँ मस्जिद के अंदर है। मस्जिद ने यह भी कहा था कि इस तरह के प्रयासों से हिंसा भड़क सकती है।



विधानसभा का धेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन से पानी डालकर उन्हें रोकने का प्रयास किया।